GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 06 Dec , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	पंख वाले आगंतुक
Page 04 **Syllabus : GS 2 & 3 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण**	आईसीजे में भारत ने जलवायु संकट के लिए विकसित देशों को दोषी ठहराया
Page 04 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	PSLV-C59 ने प्रोबा-3 उपग्रहों को सटीकता के साथ निर्धारित कक्षा में स्थापित किया
Page 10 **GS 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	क्या सीरिया की असद सरकार खतरे में है?
समाचार में	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास
Page 09 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति – संवैधानिक निकाय**	वित्त आयोग के समक्ष राज्य और चुनौतियां

GEO IAS It's about quality

Page 03 : Prelims Fact

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के पास पुलिकट झील, पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के साथ ही फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए एक जीवंत केंद्र बन गई है।

- लबालब भरी यह झील पक्षी प्रजातियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन स्थल के रूप में अपने पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है।

Winged visitors

Flamingos are back at the Pulicat Lake near Sriharikota in Andhra Pradesh. With the onset of northeast monsoon, the lake is brimming, attracting flocks of migratory birds. PTI

ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में:

- शारीरिक विशेषताएँ: गुलाबी रंग के पंख, लंबी गर्दन और पैरों वाले लंबे जलचर पक्षी। यह रंग शैवाल और क्रस्टेशियन के आहार से आता है।
- संरक्षण स्थिति: कम से कम चिंता (IUCN), लेकिन आवास के नुकसान और प्रदूषण जैसे खतरों का सामना करते हैं।
- प्रजाति विविधता: छह मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं।
- आहार: शैवाल, डायटम और छोटे जलीय जीवों को खाते हैं, भोजन को छानने के लिए अपनी विशेष चोंच का उपयोग करते हैं।
- निवास स्थान: लैगून, मुहाना और नमक के तालाब जैसे उथले जल निकायों को प्राथमिकता देते हैं।
- व्यवहार: अत्यधिक सामाजिक, वे भोजन और प्रजनन के लिए बड़े झुंड बनाते हैं।
- प्रजनन: मिट्टी के टीले के घोंसले बनाते हैं और एक अंडा देते हैं।
- महत्व: आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य के संकेतक, वे इकोटूरिज्म को आकर्षित करते हैं और जैव विविधता में योगदान करते हैं।
- भारत की ओर प्रवास: राजहंस सर्दियों के दौरान भारत की ओर प्रवास करते हैं, तथा पुलिकट झील और कच्छ के रण जैसे आर्द्रभूमि में अनुकूल भोजन और प्रजनन की स्थिति की तलाश करते हैं।

समाचार में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान भारत की स्थिति पर चर्चा की गई है, जहाँ उसने जलवायु संकट पैदा करने और जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए विकसित देशों की आलोचना की।

- भारत ने जलवायु क्षरण और अपने स्वयं के जलवायु लक्ष्यों के लिए असमान जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।
- देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपने नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में भी चिंता जताई।

जलवायु संकट पर ICJ में भारत का रुख
संकट में विकसित देशों की भूमिका

- भारत ने जलवायु संकट में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए विकसित देशों की आलोचना की।
- भारत ने कहा कि इन देशों ने वैश्विक कार्बन बजट का दोहन किया और अपने जलवायु वित्त वादों को पूरा करने में विफल रहे।
- वैश्विक उत्सर्जन में उनके न्यूनतम योगदान के बावजूद, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा भुगत रहे हैं।

जलवायु क्षरण के लिए असमान जिम्मेदारी

- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक क्षरण में असमान योगदान को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी समान रूप से वितरित की जानी चाहिए।
- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से सबसे अधिक लाभ उठाने वाले लोग अब विकासशील देशों को विकास के लिए अपने स्वयं के ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने से हतोत्साहित कर रहे हैं।

जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं हुईं

- भारत ने जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से 2009 में कोपेनहेगन COP में किए गए 100 बिलियन डॉलर के वादे को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता को उजागर किया।
- COP29 के नए जलवायु वित्त पैकेज की आलोचना अपर्याप्त और दूरगामी होने के कारण की गई, जो वैश्विक दक्षिण की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।

जलवायु लक्ष्यों के प्रति सावधानी से प्रतिबद्धता

- भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन अपने नागरिकों पर अत्यधिक बोझ डालने के बारे में चिंता व्यक्त की।
- देश ने सतत विकास लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए वैश्विक आबादी के छठे हिस्से को बनाए रखने की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ जलवायु कार्रवाई को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

At ICJ, India blames developed nations for the climate crisis

Press Trust of India
NEW DELHI

The International Court of Justice is examining legal obligations countries have to address issue of climate change

India slammed developed countries for causing the climate crisis during a landmark hearing at the International Court of Justice (ICJ) on Thursday, saying they exploited the global carbon budget, failed to honour climate finance promises and are now demanding that developing countries restrict their resource use.

The court is examining what legal obligations countries have to address climate change and the consequences if they fail.

Representing India, Luther M. Rangreji, Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, said, "If the contribution to degradation is unequal, the responsibility must also be unequal." India said developing nations were the hardest hit by climate change, despite contributing the least to it.

"The developed world, which historically contributed the most, is ironically the best equipped with the technological and economic means to address this challenge," Mr. Rangreji said.

He criticised rich countries for enjoying the benefits of fossil fuels while discouraging developing nations from using their own energy resources.

"Countries which have reaped development benefits from exploiting fossil fuels demand developing countries to not utilise the national energy resources available to them," he said.

India also slammed the lack of action on climate finance commitments.

"The $100 billion pledged at the Copenhagen COP in 2009 by developed country parties and the doubling of the contribution to the Adaptation Fund have not yet been translated into any concrete actions," India noted. It called the new climate finance package for the Global South agreed at COP29 in Baku "too little, too distant" to meet the urgent needs of developing countries.

India also reaffirmed its commitment to its climate targets under the Paris Agreement but warned against overburdening its citizens. "There is a limit on how much we burden our citizens, even when India is pursuing Sustainable Development Goals for one-sixth of humanity," it said.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

- संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग: राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देता है।
- नीदरलैंड के हेग में स्थित: "विश्व न्यायालय" के रूप में जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है।
- 15 न्यायाधीश: संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए।
- दो प्रकार के मामले: राज्यों के बीच विवादास्पद मामले और कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार कार्यवाही।
- निर्णय बाध्यकारी हैं: हालाँकि, ICJ के पास अपने निर्णयों को लागू करने का कोई तरीका नहीं है।
- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी और फ्रेंच। इन भाषाओं का उपयोग न्यायालय की कार्यवाही, दस्तावेजों और संचार के लिए किया जाता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन पर कानूनी दायित्वों की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जांच के निहितार्थों पर चर्चा करें। जलवायु वित्त और विकासशील देशों पर बोझ पर भारत का रुख जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक चुनौतियों को कैसे दर्शाता है? (150 Words /10 marks)

GEO IAS
It's about quality

इसरो के PSLV-C59 से प्रक्षेपित प्रोबा-3 मिशन, जुड़वां अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सटीक संरचना उड़ान में ईएसए की सफलता को दर्शाता है।

- इसका उद्देश्य कृत्रिम ग्रहणों के माध्यम से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है, जो उन्नत अंतरिक्ष मिशन क्षमताओं में एक मील का पत्थर है।

PSLV-C59 places PROBA-3 satellites into designated orbit with precision

Sangeetha Kandavel
SRIHARIKOTA

After being rescheduled for a day as an anomaly was detected, the Indian Space Research Organisation (ISRO) on Thursday successfully launched the PROBA-3 (Project for Onboard Autonomy) mission of the European Space Agency aboard a Polar Satellite Launch Vehicle-C59 rocket. The vehicle took off with a powerful roar precisely at 4.04 p.m. from the first launch pad at the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.

"The PSLV-C59/PROBA-3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit," ISRO Chairman S. Somanath said. The agency said the mission had successfully achieved its launch objectives, deploying the satellites into their designated orbit with precision.

Josef Aschbacher, Director-General, ESA, said: "The latest member of ESA's family of in-orbit demonstration missions, PROBA-3 comprises two spacecraft launched together which, once safely in orbit, will separate to begin performing precise formation flying... Almost instantaneously after separation, Yatharagga station in Australia started to receive the spacecraft's signal. Telemetry is flowing to ESA's mission control centre in Belgium."

Roaring start: A PSLV-C59 rocket takes off with the PROBA-3 Mission from the Satish Dhawan Space Centre on Thursday. R. RAGU

On its website, the ESA said: "A pair of spacecraft were launched together today from India with the potential to change the nature of future space missions. ESA's twin PROBA-3 platforms will perform precise formation flying down to a single millimetre, as if they were one single giant spacecraft. To demonstrate their degree of control, the pair will produce artificial solar eclipses in orbit, giving prolonged views of the Sun's ghostly surrounding atmosphere, the corona."

The ESA said the two satellites stacked together separated from their upper stage about 18 minutes after launch. The pair will remain attached while initial commissioning takes place, overseen from mission control at the European Space Security and Education Centre in Redu, Belgium.

PROBA-3 mission manager Damien Galano said, "Today's lift-off has been something all of us in ESA's PROBA-3 team and our industrial and scientific partners have been looking forward to for a long time."

Details shared by the ESA show that if PROBA-3's initial commissioning phase goes to plan, then the spacecraft pair will be separated early in the New Year to begin their individual check-outs. The operational phase of the mission, including the first observations of the corona through active formation flying, should begin in about four months.

प्रोबा-3: मुख्य जानकारी

- उद्देश्य: कृत्रिम सौर ग्रहण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, कोरोना का लंबे समय तक अध्ययन किया जा सके।
- एजेंसी: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) प्रोबा-3 की देखरेख करती है।
- अंतरिक्ष यान विन्यास: इसमें एक साथ प्रक्षेपित किए गए दो अंतरिक्ष यान शामिल हैं जो समन्वित उड़ान के माध्यम से एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए कक्षा में अलग हो जाते हैं।
- तकनीकी उन्नति: मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ गठन उड़ान का प्रदर्शन करता है, जो भविष्य के बहु-उपग्रह मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- प्रक्षेपण विवरण: श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-सी59 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
- कक्षा संचालन: प्रारंभिक कमीशनिंग कई महीनों तक चलेगी, परिचालन अवलोकन लगभग चार महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।
- महत्व: उन्नत इन-ऑर्बिट प्रदर्शनों का मार्ग प्रशस्त करता है, खगोलीय अध्ययनों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्षमताओं को बढ़ाता है।

GEO IAS
It's about quality

सीरियाई गृहयुद्ध, जो 2011 में शुरू हुआ था, में संघर्ष और सापेक्ष शांति के बीच-बीच में चरण देखे गए हैं।

- हाल ही में, इस्लामी आतंकवादियों ने एक आक्रामक अभियान शुरू किया, जिसमें अलेप्पो और हामा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे असद शासन का नियंत्रण अस्थिर हो गया।
- यूक्रेन के साथ रूस की व्यस्तता सहित भू-राजनीतिक बदलावों ने शासन की कमज़ोरियों में योगदान दिया है।

सीरिया में फिर से संघर्ष

- इस्लामी आतंकवादियों ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया में एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें अलेप्पो सहित प्रमुख क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया।
- यह 2016 के बाद से अपेक्षाकृत शांत रहने के बाद सक्रिय संघर्ष की बहाली को दर्शाता है।

क्षेत्रीय नियंत्रण में बदलाव

- 2015 में रूस के हस्तक्षेप से पहले, असद शासन केवल दमिश्क और तटीय शहरों को नियंत्रित करता था।

- 2016 के बाद, शासन ने रूसी और ईरानी समर्थन के साथ क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया, जिससे आतंकवादियों को इदलिब में धकेल दिया गया।
- पिछले सप्ताह के हमले ने आतंकवादियों को अलेप्पो और हमा के कुछ हिस्सों सहित अपने क्षेत्रीय कब्ज़े को दोगुना करने की अनुमति दी।

Is Syria's Assad regime in danger?

What was the role of Russia in the Syrian civil war back in 2016? How was the Bashar al-Assad regime able to recapture Aleppo then? Who are the Hayat Tahrir al-Sham and what is their connection to the al-Qaeda? How were the militants able to make such extensive territorial gains?

EXPLAINER

Stanly Johny

The story so far:

Islamist militants in Syria's northwest launched a surprise attack last week against the forces of President Bashar al-Assad and made dramatic territorial gains. The Syrian civil war, which broke out in 2011 amidst Arab Spring-inspired anti-government protests, had entered into a frozen stage in late 2016 after the regime recaptured most of its territories. There was relative calm, but no real peace in the Arab republic. With the latest clashes, peace has been broken and hot war has resumed.

How has Syria's control map changed in the span of a week?

In 2015, before Russian President Vladimir Putin decided to send troops to Syria, the Assad regime was on the brink of collapse. He had lost most of the population centres, except Damascus and the Alawite-dominated coastal cities. There were multiple rebel and jihadist factions such as the Free Syrian Army, Jabhat al-Nusra (al-Qaeda's Syria branch) and the Islamic State (IS). The IS was controlling eastern Syrian cities of Raqaa and Deir Ezzor as well as the ancient city of Palmyra. Al-Nusra and the Free Syrian Army were controlling parts of Idlib in the northwest. Other militant groups were controlling Hama, Homs, and even some neighbourhoods of Damascus. In the south, Daara and Quneitra were restive.

The Russian intervention played a pivotal role in turning around the civil war. While Kurdish militias, backed by the U.S., fought the IS in the east and in the Kurdish border towns, the Syrian army, backed by Russia, Iran and Hezbollah, fought other rebel groups, recapturing lost territories. For example, by December 2016, more than a year after the Russian arrival, the regime retook Aleppo, Syria's second largest city and its commercial capital. The militants continued to hold on to Idlib when the war got frozen.

Last week, the rebels launched their offensive from Idlib. Their initial objective was to capture the western neighbourhoods of Aleppo. But the ease with which they pushed the regime forces out of Aleppo's suburbs prompted them to expand the scope of the offensive and march towards the city. Within days, they captured Aleppo. They have now entered Hama, a regime stronghold. In the northeast of Aleppo, militants have captured territories from Kurdish rebels. In less than a week, the Idlib militants have more than doubled the territories they hold.

Who are the main actors?

There are three main actors in Syria today. The most important actor is the regime, which is backed by Iran and Shia militias from Iraq and Russia. The second player is the Syrian Democratic Forces (SDF), which is basically an umbrella militia group involving the People's Protection Forces (YPG), the main Syrian Kurdish militia that controls Syrian Kurdistan (Rojava). From the early stages of the civil war, the regime and the YPG had entered into a detente. The Kurds, who got their relative autonomy, and the regime forces stayed away from targeting each other. The third actor is Hayat Tahrir al-Sham (HTS), the main anti-government force that is in control of Idlib. The Turkey-backed Free Syrian Army, which is today called the Syrian National Army (SNA), is practically a sidekick of the jihadist HTS. The ongoing offensive is led by the HTS, along with the SNA.

Dramatic offence: Militants of the Hayat Tahrir al-Sham drive along a street in al-Rashideen, Aleppo province, Syria on November 29. REUTERS

The extent of the militants' advance

It took four years for Bashar al-Assad to recapture Aleppo in 2016. It took just four days for him to lose it to the Hayat Tahrir al-Sham. The regime faces a full-blown civil war, with Syria getting ready for another prolonged spell of bloodshed

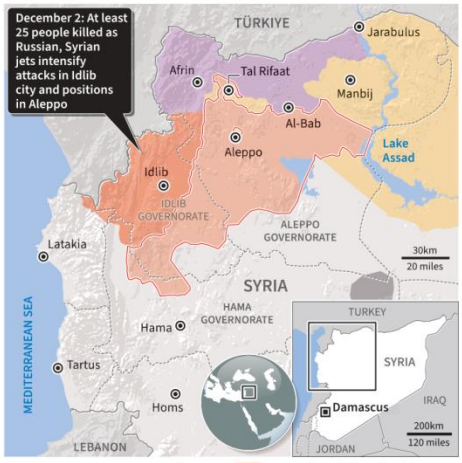

What is HTS?

The HTS is led by Abu Mohammad al-Julani, a 42-year-old Syrian militant. Julani had moved to Iraq in his early 20s to fight the American occupation of the country (2003) and joined the al-Qaeda. When the al-Qaeda in Iraq was commanded by Abu Bakr al-Baghdadi, Julani emerged as one of his close lieutenants. When Baghdadi decided to send a contingent of al-Qaeda jihadists across the border to Syria to fight President Assad after the civil war broke out, he chose Julani to lead the pack. He set up Jabhat al-Nusra. Later, Julani fell out with Baghdadi as the former wanted al-Nusra to join the Islamic State. Julani wanted to retain his group as an autonomous al-Qaeda branch in Syria.

When the world's focus shifted towards the Islamic State, Julani steadily built his empire in Idlib. The Islamic State was defeated and Baghdadi was killed, but Julani emerged as the face of the anti-regime Syrian militancy. He first changed the name of al-Nusra to Jabhat Fateh al-Sham. Later, the name was changed again to Hayat Tahrir al-Sham (HTS) as he sought to distance his group from al-Qaeda – though the HTS never renounced its Islamist ideology. Over the years, Julani's men built a parallel state in Idlib. Julani is a U.S.-designated terrorist, but, after establishing his rule over Idlib, he declared that his fight was against Mr. Assad, not against the U.S. He has not faced any major attacks from the U.S., which still has hundreds of soldiers in eastern Syria.

Why did the militants attack now?

Julani had always said that bringing down the Assad regime was one of his objectives. The Syrian regime wanted to attack Idlib and recapture the governorate. But it could not have carried out such an attack against an enclave of 3 million people without Russia's active support. Turkish President Recep Tayyip Erdogan staunchly opposed any offensive at Idlib, saying it would trigger another refugee influx into Turkey. This was also the time Russia's Mr. Putin and Mr. Erdogan entered into an entente. Russia forced Syria to accept a ceasefire, leaving Idlib in the hands of the HTS and the SNA. This led to the tense calm in Syria.

However, geopolitical dynamics have since shifted. Russia launched its invasion of Ukraine on February 24, 2022. Moscow is today preoccupied with the ongoing war, and has also withdrawn thousands of soldiers from Syria. During the height of the civil war, Qassem Soleimani, the charismatic Iranian Quds Force General, was in charge of building and deploying Shia militias in Syria that fought the anti-regime militants. Gen. Soleimani was assassinated by the Americans in January 2020. Over the past year, several senior Iranian Generals were killed in Syria by Israeli air strikes. Hezbollah, which fought on the frontlines against the rebels during the early phase of the civil war, is today busy reorganising itself after months of direct fighting with Israel. Israel's repeated air strikes in Syria over the past several years have substantially weakened Iranian, regime and Hezbollah positions in the country. These geopolitical developments provided an opportunity for the militants to launch their offensive. Without direct support from Iran, Hezbollah and Russia, Syria's troops were vulnerable. The militants, reportedly backed by Turkey, made use of that vulnerability and made swift advances to capture the whole of Aleppo.

What happens next?

It took four years for Mr. Assad to recapture Aleppo in 2016. It took just four days for him to lose it to the HTS. This is an embarrassing setback for the regime. On December 5, the militants entered Hama, the central city. They are now likely to march towards Homs. The collapse of the regime forces in the north has reinvigorated other smaller rebel groups elsewhere in the country who started attacking government positions, especially in the south. The regime faces a full-blown civil war. It's too early to rule out Mr. Assad, who survived a years-long civil war once. His regime has deep roots in the coastal regions and among the country's minorities. After the initial setback, regime forces are now coordinating with Iran for reinforcements. Thousands of fighters from Iraqi militias such as Kataib Hezbollah and Badr Organisation have already joined the battle. But the regime's inability to arrest the militant advances should set alarm bells ringing in Damascus. The militants on the other side sense a great opportunity in expanding their territorial control. Syria appears to be getting ready for another prolonged spell of bloodshed.

THE GIST

- Islamist militants in Syria's northwest launched a surprise attack last week against the forces of President Bashar al-Assad and made dramatic territorial gains.
- The HTS is led by Abu Mohammad al-Julani, a 42-year-old Syrian militant. Julani had moved to Iraq in his early 20s to fight the American occupation of the country (2003) and joined the al-Qaeda. When the al-Qaeda in Iraq was commanded by Abu Bakr al-Baghdadi, Julani emerged as one of his close lieutenants.
- Without direct support from Iran, Hezbollah and Russia, Syria's troops were vulnerable. The militants, reportedly backed by Turkey, made use of that vulnerability and made swift advances to capture the whole of Aleppo.

संघर्ष में मुख्य अभिनेता

- शासन: रूस, ईरान और शिया मिलिशिया द्वारा समर्थित, यह नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।
- सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ): अमेरिका द्वारा समर्थित कुर्द मिलिशिया, पूर्वोत्तर सीरिया को नियंत्रित कर रहे हैं।
- हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस): सीरियाई राष्ट्रीय सेना (एसएनए) के साथ वर्तमान आक्रमण का नेतृत्व करने वाला एक जिहादी समूह।

HTS: एक प्रमुख उग्रवादी समूह

- HTS अल-कायदा की सीरियाई शाखा से विकसित हुआ, जिसका नेतृत्व अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी कर रहा है।
- यह इदलिब को नियंत्रित करता है और इसने अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि असद शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई की घोषणा की है।

आक्रमण को प्रेरित करने वाले भू-राजनीतिक कारक

- रूस का यूक्रेन पर ध्यान और सीरिया में कम उपस्थिति ने शासन के समर्थन को कमजोर कर दिया।
- ईरान और हिजबुल्लाह, असद के प्रमुख सहयोगी, बाहरी संघर्षों और हवाई हमलों के कारण बहुत अधिक तनावग्रस्त या कमजोर हो गए हैं।
- तुर्की ने कथित तौर पर शासन की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उग्रवादियों का समर्थन किया।

भविष्य के लिए निहितार्थ

- विद्रोहियों की बढ़त सीरिया में गृहयुद्ध के संभावित पुनरुत्थान का संकेत है।
- शासन बल इराकी मिलिशिया से सुदृढीकरण के साथ फिर से संगठित हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक रक्तपात की संभावना है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर सीरियाई गृहयुद्ध के प्रभाव पर चर्चा करें। (150 words/10m)

GEO IAS
It's about quality

In News : North-East Region Development

पीएम-देवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देती है।

- इसके पूरक के रूप में, उन्नति पहल औद्योगीकरण, रोजगार सृजन और लचीलेपन का समर्थन करती है, जिससे क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

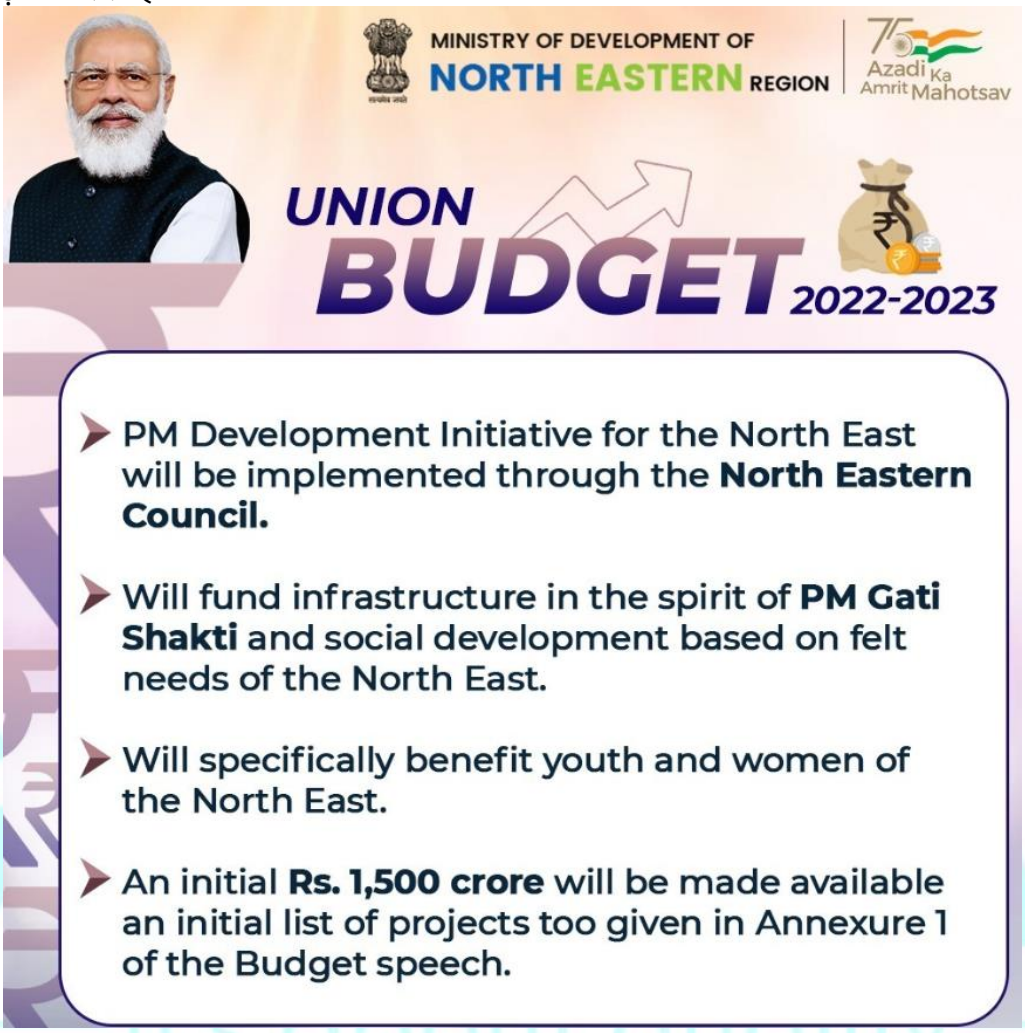

पीएम-देवाइन योजना अवलोकन

- केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया।
- शुरुआती परिव्यय ₹1,500 करोड़ था, जिसे बाद में वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर ₹6,600 करोड़ कर दिया गया।

- **उद्देश्य:**
  - o पीएम गति शक्ति के साथ संरेखित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि प्रदान करना।
  - o पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास पहलों का समर्थन करता है।
  - o युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

- विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को संबोधित करता है।

- **प्रगति:**
  - नवंबर 2024 तक ₹4,857.11 करोड़ की 35 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

एनईआर में औद्योगिकीकरण पहल

- **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NIDS):**
  - 2017 में शुरू की गई और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुई।
  - इसका उद्देश्य एनईआर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है।
  - उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति) योजना:
  - 9 मार्च, 2024 को शुरू की गई।
  - बुनियादी ढांचे, रोजगार और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

- **दिए गए प्रोत्साहन:**
  - पूंजी निवेश प्रोत्साहन।
  - पूंजी ब्याज अनुदान।
  - विनिर्माण और सेवा से जुड़े प्रोत्साहन।

एनईआर विकास के लिए बजटीय आवंटन

- गैर-छूट वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने सकल बजटीय आवंटन का 10% एनईआर के लिए आवंटित करना आवश्यक है।
- 2019-20 और 2023-24 के बीच ₹3,53,412 करोड़ का अनंतिम व्यय हुआ।

GEO IAS
It's about quality

Page : 08 Editorial Analysis

States and the challenge before the Finance Commission

M.K. Stalin

President of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the Chief Minister of Tamil Nadu

The Government of Tamil Nadu recently hosted the Sixteenth Finance Commission, which was chaired by Arvind Panagariya. With its distinguished experts from various fields, the Commission is uniquely positioned to address the critical fiscal challenges facing India and rectifying the skewness in the relationship between the States and the Union.

Opportunities from global changes

The decisions taken by this Finance Commission will not only shape the fiscal fate of the nation for the next five years but will also influence India's economic trajectory in the decades to come. The Sixteenth Finance Commission's work coincides with significant shifts in global economic trends. Concepts such as "friendshoring" and "reshoring" are reshaping international trade and investment patterns. These trends present a unique opportunity for India and Tamil Nadu. To seize these opportunities, the critical challenge for the Finance Commission lies in striking a balance between equitable redistribution and incentivising growth in high-performing States such as Tamil Nadu.

Since 1951, when the first Finance Commission was formed, each Finance Commission has adapted its own approach towards the fiscal challenges of its time. Every Commission has sought to achieve an equitable redistribution of resources by increasing the share of States under vertical devolution and channelling funds to less-developed States through horizontal devolution.

But there have been clear gaps between their declared objectives and outcomes; therein lies our case for a new and fair system of distribution of resources. For instance, while the Fifteenth Finance Commission awarded the vertical share of the divisible pool to the States as 41%, the effective devolution to States in the first four years of the award period amounted to only 33.16% of the Union's gross tax revenue. The unprecedented levying of cess and surcharges by the Union is the fundamental reason for this effective decline in devolution.

There needs to be a progressive resource allocation methodology for performing States such as Tamil Nadu

Hike States' share, incentivise performers

The States, which are near to people, bear substantial developmental expenditures, and, hence, their share should be further increased substantially. The financial strain on the States has been particularly severe due to increases in counterpart funding for centrally sponsored schemes on the one side and inadequate devolution on the other side. Hence, a fair and equitable share for States would be 50% devolution of the gross central taxes, allowing States greater fiscal autonomy in funding and implementing locally relevant schemes.

On horizontal devolution, it is evident that the redistribution policy followed for the first four and a half decades in our country has yielded limited results in driving real growth. Hence, the fundamental question would be this: should the focus be on a smaller national pie with a larger share for less-developed States or a larger national pie with equitable distribution that provides greater absolute resources for all? The answer is difficult, yet a more balanced approach would ensure a larger national economic pie, allowing for reasonable shares for less-developed States and adequate resources for progressive States to continue their upward trajectory. This would clearly necessitate a progressive resource allocation methodology for the performing States so as to allow them to fulfil their potential to be India's growth engines.

Unique challenges in progressive States

Amidst this, it is also important to note that progressive States such as Tamil Nadu also face unique challenges in demography and urbanisation. With a median age higher than the national average, the State's capacity to generate consumption-based tax revenue is declining, even as the costs of supporting an aging population are rising. It is imperative to ensure that such States do not fall into the "middle-income trap", where growth stagnates and they "grow old before becoming rich". Next, the challenges due to urbanisation in fast-growing States merit adequate addressal. A State like Tamil Nadu is witnessing the fastest rate of urbanisation in the country, due to which it will have a 57.30% urban population in 2031, against the expected national average of 37.90%. The resources for fulfilling the infrastructure needs of urbanisation should be earmarked to ensure the long-term sustainability of our growth.

We should keep in mind that the mandate of the Commission goes beyond fiscal arithmetic. It is about envisioning a future where every State contributes to and benefits from the nation's progress. Whether it is fostering manufacturing, addressing urbanisation challenges, or ensuring climate resilience, the Commission's decisions will impact millions of lives and determine the trajectory of the country's destiny, to take its place among the world's leading economies.

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति – संवैधानिक निकाय

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-2 2021): भारत के 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में किस प्रकार मदद मिली है? (150 words/10m)

UPSC Mains Practice Question: संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय असमानताओं को दूर करने में सोलहवें वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उभरती आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन आवंटन को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाना चाहिए? (150 Words /10 marks)

संदर्भ :

- लेख में सोलहवें वित्त आयोग और राज्यों तथा संघ के बीच वित्तीय चुनौतियों तथा संसाधन वितरण को संबोधित करने में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई है।
- यह वैश्विक आर्थिक बदलावों, तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों तथा संतुलित वित्तीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

आयोग के अधिदेश का अवलोकन

- अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में सोलहवें वित्त आयोग की हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा मेजबानी की गई थी।
- इस आयोग को महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने तथा राज्यों और संघ के बीच निष्पक्ष संबंध सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- इसके निर्णय अगले पाँच वर्षों के लिए भारत की वित्तीय नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे तथा देश के दीर्घकालिक आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देंगे।

वैश्विक परिवर्तनों से उत्पन्न अवसर

- "फ्रेंडशोरिंग" तथा "रीशोरिंग" सहित आर्थिक प्रवृत्तियों में वैश्विक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को नया रूप दे रहे हैं।
- ये प्रवृत्तियाँ भारत को अपनी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं।
- वित्त आयोग की चुनौती तमिलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विकास को प्रोत्साहित करते हुए संसाधनों के समान पुनर्वितरण को संतुलित करना है।

संसाधन वितरण में चुनौतियाँ

- 1951 में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना के बाद से, राज्यों के बीच संसाधनों को समान रूप से पुनर्वितरित करने का लगातार प्रयास किया गया है।
- हालाँकि, आयोग के घोषित लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों के बीच विसंगतियाँ बनी हुई हैं।
- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा विभाज्य पूल का 41% राज्यों को आवंटित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप केवल 33.16% प्रभावी हस्तांतरण हुआ, क्योंकि संघ की उपकर और अधिभार पर बढ़ती निर्भरता के कारण हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न हुई।

राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना

- जो राज्य पर्याप्त विकास व्यय का प्रबंधन करते हैं, उन्हें सकल केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए - जो लगभग 50% होने का सुझाव दिया गया है।
- इससे राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता मिलेगी, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली योजनाओं को निधि देने और लागू करने में सक्षम होंगे।

- क्षैतिज हस्तांतरण की वर्तमान नीति ने विकास को गति देने में सीमित परिणाम दिए हैं, और कम विकसित और उच्च प्रदर्शन करने वाले दोनों राज्यों को फलने-फूलने देने के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रगतिशील राज्यों में चुनौतियाँ

- तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बढ़ती उम्र की आबादी और बढ़ता शहरीकरण।
- तमिलनाडु की बढ़ती उम्र की जनसांख्यिकी खपत-आधारित कर राजस्व उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को सीमित करती है, जबकि बढ़ती उम्र की आबादी को सहारा देने की लागत वहन करती है।

आयोग की व्यापक भूमिका

- वित्त आयोग का अधिदेश केवल राजकोषीय अंकगणित के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा देने के बारे में है, जहाँ हर राज्य राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे और उससे लाभान्वित हो।
- आयोग के निर्णयों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें विनिर्माण, शहरीकरण और जलवायु लचीलापन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की क्षमता को आकार देंगे।

सोलहवाँ वित्त आयोग:

- गठन: 31 दिसंबर, 2023
- अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया (नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष)
- उद्देश्य: यह सुझाव देना कि भारत के कर राजस्व को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कैसे साझा किया जाना चाहिए।
- कार्यकाल: 5 वर्ष (1 अप्रैल, 2026 से शुरू)
- मुख्य विचार: राजकोषीय स्थिरता, आर्थिक विकास और राज्यों के बीच समानता।
- पिछला आयोग: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी हैं।
- महत्वपूर्ण कार्य: भारत की समेकित निधि से राज्यों को वित्तीय सहायता देने के सिद्धांतों का निर्धारण करना।
- अतिरिक्त भूमिका: स्थानीय सरकारों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) का समर्थन करने के लिए समेकित निधि के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाना।
- वर्तमान स्थिति: आयोग जानकारी एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया में है।